



कोई भी क्रोधित हो सकता है। यह आसान है, लेकिन सही व्यक्ति से सही सीमा में सही समय पर और सही उद्देश्य के साथ सही तरीके से क्रोधित होना सभी के बस की बात नहीं है और यह आसान नहीं है।

-अरस्तु

जिद...सच की



www.4pm.co.in



www.facebook.com/4pmnewsnetwork



@Editor_SanjayS



4pm NEWS NETWORK

● वर्ष: 12 ● अंक 221 पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, गुरुवार 18 सितम्बर, 2026

भारत ने टी20 सीरीज में किया लीन... 7 गृहमंत्री शाह का बयान, यूसीसी... 3 भाजपा सरकार में निर्माण से... 2

महाराष्ट्र की कहानी बंगाल में रिपीट!

ममता का घास-फूल चुनाव चिन्ह फ्रीज

- » अब नई पहचान से लड़ने होंगे उपचुनाव
- » राहुल गांधी की ललकार वोट चोरी के बाद अब पार्टी चोरी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। 1998 में जब तृणमूल कांग्रेस बनी थी तब ममता बनर्जी ने पार्टी के लिए एक ऐसा चुनाव चिन्ह चुना जो उनके नाम और जमीनी राजनीति की छवि से जुड़ा था। दो फूल और घास का वह निशान धीरे धीरे यह सिर्फ एक चुनाव चिन्ह नहीं रहा बल्कि बंगाल की राजनीति में तृणमूल की पहचान बन गया। करीब 28 साल बाद कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां वही चुनाव चिन्ह पार्टी के सबसे बड़े संगठनात्मक विवाद के बीच खड़ा है।

अब चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को नई आधिकारिक पहचान सौंप दी है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम आवंटित किया गया है और आगामी चुनावी मैदान में वे फुटबॉल खिलाड़ी के चुनाव चिन्ह के साथ उतरेंगे। वहीं दूसरी तरफ, अरुण रॉय के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंद्वी गुट को भी चुनाव आयोग द्वारा एक नई राजनीतिक पहचान दी गई है। इससे पहले चुनाव आयोग ने अंतरिम आदेश में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और फलावर एंड ग्रास चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया है।

28

साल बाद कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां वही चुनाव चिन्ह पार्टी के सबसे बड़े संगठनात्मक विवाद के बीच खड़ा है।

“

हर बार एक ही पैटर्न बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर एक पार्टी को तोड़ते हैं। फिर उसका चुनाव चिन्ह छीन लिया जाता है।

राहुल गांधी

मामला उस फूल और घास का है जिसे बंगाल की राजनीति में एक पहचान के तौर पर देखा जाता रहा है।

दोनों को नए चुनाव चिन्ह आवंटित

“

फैसला नहीं होता ममता बनर्जी और उनके विरोधी गुट दोनों ही इस नाम और इस आरक्षित चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकते

“

अब बंगाल में तृणमूल के भीतर संगठनात्मक नियंत्रण को लेकर विवाद के बीच चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को पुराने नाम और निशान से फिलहाल टूट कर दिया है।

सवाल सिर्फ एक चुनाव चिन्ह का नहीं है

पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश के बाद तृणमूल कांग्रेस का आधिकारिक नाम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और उसका आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह फिलहाल फ्रीज कर दिया गया है। ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले दोनों गुट आगामी उपचुनाव में इस नाम और निशान का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आयोग ने दोनों पक्षों से वैकल्पिक नाम और मुक्त चुनाव चिन्हों के विकल्प मांगे हैं। यानी बंगाल की सियासत में अब सवाल यह नहीं है कि कौन किसके साथ है सवाल यह भी है कि जिस तृणमूल के नाम पर वोट मांगा जाएगा वह तृणमूल आखिर होगी किसकी और जिस निशान पर दशकों से वोट पड़ता आया है अगर वही निशान ईवीएम पर नहीं होगा तो मतदाता के सामने क्या होगा?

ममता ने फैसले पर नाराजगी जाहिर की है

ममता बनर्जी ने आयोग के फैसले पर विरोध दर्ज कराया है। दूसरी तरफ ऋतब्रत बनर्जी गुट ने फैसले का स्वागत किया है और इसे पार्टी संगठन पर किसी एक व्यक्ति के उत्तराधिकार के दावे के संदर्भ में पेश किया है। और इसी बीच राहुल गांधी मैदान में

उतरते हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के फैसले को लेकर बीजेपी और आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इसे विपक्षी दलों को कमजोर करने की व्यापक राजनीति से जोड़ा है। सवाल बड़ा है और उसका उत्तर उससे भी बड़ा कि क्या यह सिर्फ तृणमूल की अंदरूनी लड़ाई है या फिर भारतीय राजनीति में

पार्टी संगठन नाम और चुनाव चिन्ह के रिश्ते की एक नई कहानी लिखी जा रही है क्योंकि मामला सिर्फ ममता बनर्जी को नहीं है। मामला उस फूल और घास का है जिसे बंगाल की राजनीति में एक पहचान के तौर पर देखा जाता रहा है। और अब वही निशान फिलहाल चुनाव आयोग की फाइल में बंद है।

महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हो चुका है

महाराष्ट्र में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भीतर टूट के बाद नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर जो कानूनी सियासी संघर्ष चला उसने देश की राजनीति में एक नया अध्याय खोला। अब बंगाल में तृणमूल के भीतर संगठनात्मक नियंत्रण को लेकर विवाद के बीच चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को पुराने नाम और निशान से फिलहाल टूट कर दिया है। महाराष्ट्र और बंगाल के मामलों के कानूनी तथ्य अलग हैं लेकिन एक तस्वीर दोनों जगह दिखाई देती है पार्टी के भीतर टूट और उसके बाद नाम तथा चुनाव चिन्ह पर कब्जे की लड़ाई। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने पहले शिवसेना और एनसीपी के अलग अलग गुटों को लेकर फैसले किए थे वहीं मौजूदा बंगाल मामला अभी अंतरिम चरण में है।

नंदीग्राम फिर केंद्र में

बंगाल की राजनीति में नंदीग्राम कोई सामान्य विधानसभा सीट नहीं है यही जगह है कि छह अक्टूबर के उपचुनाव से पहले तृणमूल के नाम और निशान पर आया यह आदेश राजनीतिक रूप से खास महत्व रखता है। उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और चुनाव आयोग को दोनों गुटों की पहचान स्पष्ट करनी है। इसी कारण आयोग ने अंतरिम व्यवस्था के तहत दोनों पक्षों से नए विकल्प मांगे हैं।

अब लड़ाई सिर्फ यह नहीं होगी कि कौन चुनाव जीतेगा एक और लड़ाई होगी कौन अपनी राजनीतिक पहचान मतदाता तक पहुंच पाता है कौन कार्यकर्ताओं को एकजुट रखता है और किस गुट के साथ संगठनात्मक ढांचा खड़ा रहता है क्योंकि मतदाता पुराने फूल घास के बजाय नए नाम और नए निशान को उसी राजनीतिक पहचान से क्या जोड़ पाएगा। इन सवालों के जवाब उपचुनाव के दौरान ही साफ होंगे।

राहुल की ललकार

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तृणमूल कांग्रेस का नाम और सिंबल फ्रीज करने पर भाजपा के साथ ही चुनाव आयोग पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने शिवसेना, एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस का जिक्र करते हुए भाजपा और चुनाव आयोग पर पार्टी चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वोट चोरी। सरकार चोरी। अब पार्टी चोरी - ये हमारे लोकतांत्रिक पतन के प्रतीक बन गए



है। राहुल गांधी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, पहले शिवसेना, फिर एनसीपी और अब तृणमूल कांग्रेस। हर बार एक ही पैटर्न बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर एक पार्टी को तोड़ते हैं। फिर उसका चुनाव चिन्ह छीन लिया जाता है। जब पूरी की पूरी पार्टी चोरी हो सकती है तो

करोड़ों भारतीयों के वोट चोरी होना भी हैरानी की बात नहीं। वोट चोरी। सरकार चोरी। अब पार्टी चोरी ये हमारे लोकतांत्रिक पतन के प्रतीक बन गए हैं। ईसीआई की सवैधानिक जिम्मेदारी जनादेश की रक्षा करना है मगर उल्टा वो उन ताकतों की मदद कर रहा है जो जनता के फैसले को ही पलट देते हैं। यह लड़ाई सिर्फ ममता बनर्जी जी की नहीं है। यह हर राजनीतिक दल हर मतदाता की लड़ाई है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहता है।

भाजपा सरकार में निर्माण से पहले टूट फूट शुरू हो जाती है : अखिलेश

» सपा प्रमुख ने टूटे एक्सप्रेसवे का दिखाया वीडियो

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार में बने एक्सप्रेसवे की हालत को लेकर उस पर करारा प्रहार किया है। सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा सरकार में किसी प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य पूरा बाद में होता है गिरना पहले शुरू हो जाता है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और उसका मेंटीनेंस अभी भी जारी है।

अखिलेश यादव सपा कार्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भाजपा सरकार में बने लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के टूटने को लेकर वीडियो भी दिखाया और कहा कि ऐसा लगता है कि दिल्ली और लखनऊ वालों के बीच मुकाबला चल रहा है कि किसके पास ज्यादा मुनाफा होगा। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में बने रिवरफ्रंट और अन्य निर्माण की क्वालिटी सबसे अच्छी है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का डिजाइन सबसे अच्छा है और भाजपा के लोग अब इसे खराब कर रहे हैं। रिवरफ्रंट पर लगे फव्वारे भी वैसे ही हैं। बच्चों को दिए गए लैपटॉप भी अभी वैसे के वैसे हैं।



सपा सरकार बनने पर भगवान विश्वकर्मा जयंती पर राजकीय अवकाश बहाल करेंगे

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेसवार्ता करते हुए घोषणा की है कि मविष्य में उत्तर प्रदेश में दोबारा समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर भगवान विश्वकर्मा जयंती पर राजकीय अवकाश पुनः बहाल किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट पर भगवान विश्वकर्मा के मध्य मंदिर के निर्माण का भी वादा किया। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह खादू श्याम जी के मंदिर का निर्माण नियम और कानूनों के तहत किया गया है, उसी तर्ज पर सब मिलकर भगवान विश्वकर्मा का मध्य मंदिर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि आज भी किसी निर्माण कार्य की शुरुआत में सबसे पहले भगवान विश्वकर्मा की ही पूजा की जाती है।

पूर्व मंत्री राम आश्रय कुशवाहा की सपा में हुई वापसी

पूर्व मंत्री राम आश्रय कुशवाहा माजपा को छोड़कर सपा में शामिल हो गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुझे आज भी नेताजी (मुलायम सिंह यादव) अपने बीच महसूस होते हैं। उन्होंने सपा की सदस्यता ली और कहा कि जब तक अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना देते वो घर नहीं बैठेंगे।

यूपीआई रुपये ऐंठने वाली योजना

अखिलेश यादव ने यूपीआई से मुग़तान करने पर व्यापारियों पर लगाए गए टैक्स पर कहा कि यूपीआई रुपये ऐंठने वाली योजना है। उन्होंने कहा कि चुंगीजीवी लोगों को रुपये ऐंठने वाली योजना बंद कर देना चाहिए। ये लोग उद्योगपतियों की जेबें भरने की योजनाएं बनाते हैं।

पेड़ लगाने का आंकड़े फर्जी

अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में 200 करोड़ पेड़ लगाने का दावा किया है। सपा सरकार में हमने एक हजार एकड़ पर एक लाख 34 हजार पेड़ लगवाए थे। सरकार कह रही है कि उन्होंने 200 करोड़ पौधे लगवाए हैं तो वो बताएं कि वो जमीन कहाँ है जहाँ 200 करोड़ पौधे लगाए गए थे।

सीधे रास्ते पर चले सरकार नहीं तो आंदोलन: टिकैत

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुजफ्फरनगर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में विशाल किसान-मजदूर महापंचायत का आयोजन किया गया। इस बैठक में राकेश टिकैत और नरेश टिकैत भी शामिल हुए, जिसमें किसानों ने गन्ने के दाम बढ़ाने, एमएसपी गारंटी कानून, बिजली, जमीन के सर्किल रेट बढ़ाने और किसानों से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा की।

मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में हुई इस रात्रि महापंचायत में आसपास के कई जनपदों से बड़ी संख्या में किसान और कार्यकर्ता पहुंचे थे। यूपी में पहली बार इस तरह रात्रि महापंचायत का आयोजन हुआ है। देर रात तक किसानों ने विभिन्न मुद्दों पर मंथन किया और इसके बाद किसानों और कार्यकर्ताओं के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस पंचायत को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि लड़ाई सिर्फ दिन में नहीं बल्कि, रात में भी लड़ी जाती है। उन्होंने इसे किसानों और कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग से जोड़ते हुए कहा कि लंबे समय से उनकी रात में इस तरह की बैठक नहीं हुई थी। टिकैत ने इस दौरान केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि सरकार को सीधे रास्ते पर चलना चाहिए, नहीं, तो आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इसी तरह की बैठकें प्रदेश के दूसरे जिलों में भी आयोजित की जाएंगी और वैचारिक क्रांति के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा।

टिकैत ने किसानों की मांगों को लेकर गन्ने के दाम बढ़ाने, एमएसपी गारंटी कानून लागू करने, बिजली संशोधन बिल खत्म करने और जमीन के सर्किल रेट बढ़ाने की मांग दोहराई। उन्होंने चीनी के बढ़ते दामों को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए।

मेडिकल कॉलेज में आरक्षण पर रोक से मायावती नाराज

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट पैरवी करे योगी सरकार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। यूपी के सहारनपुर, अंबेडकर नगर, कन्नौज और जालौन में बने चार स्पेशल कंपोनेंट प्लान वाले मेडिकल कॉलेज में एससी वर्ग के 50 फीसद आरक्षण पर हाईकोर्ट ने पाबंदी लगा दी है, जिस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सरकार ने इस मुद्दे पर मजबूती से पैरवी नहीं की, उन्होंने इन कॉलेजों में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील किए जाने की मांग की है।

बसपा मुखिया मायावती ने कहा कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत बने ये मेडिकल कॉलेज एससी समाज के कल्याण के लिए बने हैं। जिसमें एससी वर्ग के लिए सामान्य वर्ग से अलग 50 फीसद आरक्षण की व्यवस्था है। लेकिन, सरकार ने एससी वर्ग के आरक्षण को लेकर कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं की इसलिए हाईकोर्ट ने इस पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन, सरकार को इसके खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करनी चाहिए। बसपा अध्यक्ष ने लिखा- बहुचर्चित सामाजिक न्याय की जरूरत व मांग भी यही है कि यूपी सरकार माननीय न्यायालय में यदि



इस बात की पुरजोर पैरवी करती कि एससी समाज के हित व कल्याण हेतु 'स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान' के धन से जल्ला सहारनपुर, अम्बेडकरनगर, कन्नौज व जालौन में बनाये गये मेडिकल कालेजों में एससी वर्ग हेतु अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था 50 प्रतिशत के सामान्य आरक्षण से अलग है। और इस व्यवस्था से स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की भरपूर उपयोगिता साबित होती है, तो शायद माननीय कोर्ट इस पर जरूर सकारात्मक विचार करता और इस पर रोक नहीं लगाता। किन्तु अब जबकि मा। हाईकोर्ट ने इस पर पाबंदी लगा दी है और मेडिकल दाखिला भी अब यहाँ इससे प्रभावित है, तो ऐसे में यूपी सरकार तुरन्त मा। सुप्रीम कोर्ट में आपेक्षित राहत के लिये अपील करे तो यह उचित होगा।



बामुलाहिजा

कविता, हसन जैदी

‘सेवा संकल्प अभियान’ पर बिहार में सियासत

» लालू के बेटे-बेटी भाजपा पर तीखा हमला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर बिहार में सियासत भी शुरू हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए बाढ़ की स्थिति का मुद्दा उठाया है।

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के 15 जिलों में 50 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और ऐसे समय में भाजपा प्रधानमंत्री का जन्मदिन मना रही है। वहीं, रोहिणी आचार्य ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भाजपा पर तंज कसा है।

महाअवतारी जी’ के लिए सिर्फ एक दिन, महज एक घंटे तक ही दीया जलाना पर्याप्त नहीं है : रोहिणी आचार्य

रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री के जन्मदिन के आयोजन को लेकर व्यंग्य किया। उन्होंने लिखा कि ‘महाअवतारी जी’ के लिए सिर्फ एक दिन, महज एक घंटे तक ही दीया जलाना पर्याप्त नहीं है...!! उन्होंने आगे लिखा कि पूछता है हिंदुस्तान... ब्रह्मांड के स्वयंभू अधिपति, नौन-बायोलॉजिकल, जवाबदेही मुक्त, जुमले आजम, मेलेडी मैन ‘महाअवतारी जी’ के प्रकटोत्सव (अवतारण दिवस) का जश्न कब तक मनाया है? रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में आगे व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि सिर्फ एक दिन और एक घंटे तक दीया जलाना पर्याप्त नहीं है। उनके अनुसार, उत्सव प्रतिदिन 24 घंटे और पूरे वर्ष चलते रहना चाहिए अन्यथा महाअवतारी जी की लीला का बखाना पूरा नहीं हो पाएगा। उनके नाम का जाप करने वाले झांसेबाजों, जुमलेबाजों, गाल बजाने वाले भक्तों का जीवन निर्दोषक हो जाएगा।



उबल इंजन सरकार मोदी के प्रचार में सौ करोड़ रुपये नाले में प्रवाहित करेगी : तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आयोजित होने वाले ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साधा था। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया था कि बिहार सरकार प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर ‘आशीर्वाद का दीया’ नाम से सरकारी कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उन्होंने दावा किया कि इस कार्यक्रम में बिहार जैसे गरीब राज्य में 100 करोड़ रुपये दीया, बाती और तेल पर खर्च किए जाएंगे। तेजस्वी यादव ने बिहार में बाढ़ की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा था कि राज्य में बाढ़ से 49 लाख लोग प्रभावित हैं।



नगर निकायों पर कब्जे के लिए बीजेपी पार्षदों को करोड़ों की रिश्त दे रही है : गहलोत

» राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री बोले-सीएमओ का एक आईएएस कलेक्टर और एसडीएम पर अनुचित दबाव डाल रहा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि नगर निकायों पर कब्जे के लिए बीजेपी पार्षदों को करोड़ों की रिश्त दे रही है। उन्होंने दावा किया कि सीएमओ का एक आईएएस अफसर कलेक्टर और एसडीएम पर अनुचित दबाव डाल



रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जयपुर वार्ड उपचुनाव में बीजेपी की हार को जनता का कड़ा संदेश बताया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 सितंबर को आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय का एक आईएएस अधिकारी कलेक्टरों और

सब-डिविजनल मजिस्ट्रेटों (एसडीएम) पर दबाव डाल रहा है ताकि राज्य भर के नगर निकायों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बोर्ड बन सकें। गहलोत ने दावा किया कि भाजपा सदस्यों को चेयरमैन और मेयर बनाने के लिए निर्दलीय और विपक्षी पार्षदों को रिश्त के तौर पर करोड़ों रुपये बांटे जा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यह पैसा भ्रष्टाचार के जरिए वसूला जाएगा, जिसका बोझ आखिरकार जनता पर ही पड़ेगा। एक पोस्ट में गहलोत ने कहा कि राजस्थान में लोकतंत्र को खुलेआम लूटा जा रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय का एक आईएएस अधिकारी कलेक्टरों और एसडीएम को धमका रहा है कि वे किसी भी तरह भाजपा का बोर्ड बनवाएं। भाजपा सदस्यों को चेयरमैन और मेयर बनाने के लिए निर्दलीय और विपक्षी पार्षदों को करोड़ों रुपये की रिश्त दी जा रही है जो मना करते हैं, उन्हें पुलिस जबरदस्ती उठा ले जाती है और डराती-धमकाती है। उन्होंने इन पदों को पाने के लिए भारी निवेश करने वालों की ईमानदारी पर सवाल उठाया कि जरा सोचिए जो व्यक्ति मेयर या चेयरमैन बनने के लिए करोड़ों खर्च करता है—क्या वह जनता की सेवा करेगा या अपना लगाया हुआ पैसा वसूलने में लगा रहेगा? रिश्त जितनी बड़ी होगी, वसूली भी उतनी ही बड़ी होगी, और यह वसूली सड़कों, जमीन के आवंटन, नालियों और जनता के लिए होने वाले हर छोटे-बड़े सार्वजनिक काम की फाइलों से की जाएगी। अगले पाँच सालों तक, जनता को अपने ही शहर में हर काम के लिए भारी रिश्त देनी होगी। यह सिर्फ बीजेपी की राजनीति नहीं है। यह आपकी जेब पर सीधी डकैती है। जनता को अब जागना होगा, वरना यह लूट निश्चित रूप से आपके दरवाजे तक पहुँचेगी। इस बीच, राजस्थान में विपक्ष के नेता टीका राम जुली ने जयपुर के उन चार वार्डों में भजपा की 4-0 से हार पर प्रतिक्रिया दी, जहाँ दोबारा वोटिंग हुई थी। उन्होंने कहा कि नतीजों ने साफ संदेश दिया है कि सत्ता में बैठे लोगों की कोशिशों के बावजूद जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। जुली ने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र जनता के भरोसे पर टिका होता है और पुलिस, प्रशासन व अधिकारियों का दबाव जनता के फँसले से ऊपर नहीं हो सकता। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि जनता की राय के सामने सत्ता का अहंकार, तानाशाही और पूरी सरकारी मशीनरी आखिरकार बौनी साबित होती है—जयपुर ने आज यह दिखा दिया।

गृहमंत्री शाह का बयान, यूसीसी पर फिर मचेगा घमासान

डीएमके, राजद व कांग्रेस ने कहा- असंवैधानिक

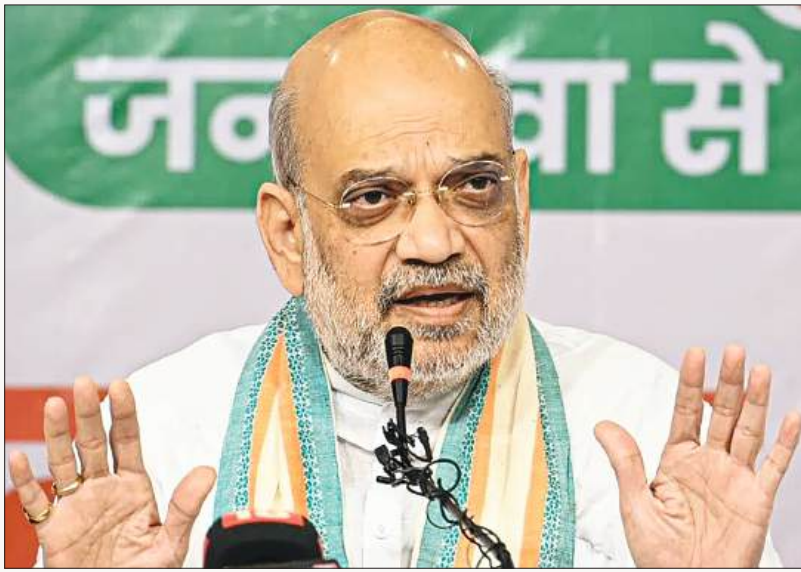
» भाजपा पर विपक्ष का तीखा प्रहार » सहयोगी दलों ने भी बीजेपी को घेरा

» नीतीश कुमार की पार्टी बोली- बिहार में यह सब नहीं चलेगा

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। गृहमंत्री अमितशाह के इस बयान की भाजपा शासित राज्यों में 2029 तक समान अचार संहिता लागू कर दी जाएगी के बाद सियासी घमासान मच गया। विपक्ष तो भाजपा को इसको लेकर घेर ही रही है उसके सहयोगी भी इसपर संभलकर चलने को कह रहे हैं। इस मामले में जहां भाजपा शिवसेना, टीडीपी को साथ मिल रहा है वहीं जदयू, लोजपा रामविलास उसे संभल कर चलने को कह रह रहे हैं। जबकि विपक्ष में कांग्रेस, राजद, सपा व डीएमके उस पर हमलावर हैं। विपक्ष का कहना है मानवीय मुद्दों से भटकाकर भाजपा लोगों को गुमराह कर रही है।

बिहार में तो राजद ने जदयू को भाजपा से सरकार से हट कर खुद के साथ सरकार बनाने का आफर कर दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी-एनडीए शासित 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता) लागू करने के गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सत्ताधारी गठबंधन दो फाड़ नजर आ रहा है। एनडीए के कुछ सहयोगी दलों ने यूसीसी का सपोर्ट किया है लेकिन वहीं कुछ दलों ने इसे लेकर विरोध जाहिर किया है। यूसीसी का विरोध करने वाले दलों का कहना है कि इस मुद्दे पर व्यापक विचार विमर्श होना चाहिए। तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी), शिव सेना और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) ने यूसीसी का समर्थन किया है, जबकि जनता दल (यूनाइटेड) और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) जैसे बीजेपी सहयोगियों ने सतर्क रुख अपनाया है।



व्यापक विचार विमर्श के बाद फैसला लेंगे: चिराग पासवान

वहीं, लोजपा (रामविलास) प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि भारत का सामाजिक ताना-बाना विविधतापूर्ण है और अलग-अलग वर्गों की अपनी नागरिक परंपराएं और रीति-रिवाज हैं। उन्होंने संविधान में अनुसूचित जनजातियों को मिली विभिन्न छूट का उल्लेख करते हुए

कहा कि उनकी पार्टी समानता और विविधता दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। यूसीसी का प्रारूप सार्वजनिक होने, सभी हितधारकों के हितों का



अलोकन और व्यापक विचार-विमर्श होने के बाद पार्टी अपना मत रखेगी। भारत का सामाजिक ताना-बाना विविधतापूर्ण है और अलग-अलग वर्गों की अपनी नागरिक परंपराएं और रीति-रिवाज हैं। पार्टी अनुसूचित जनजातियों की समानता और विविधता दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है।

यूपी में चुनाव से पहले आएगा यूसीसी

यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर योगी सरकार के मंत्री और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार यूसीसी लागू करने के लिए तैयार है। बीजेपी ने लोक सभा चुनाव के दौरान संकल्पन जारी किया था, जिसमें हमने UCC को प्रमुखता से शामिल किया था। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि हमारी पार्टी का मानना है कि जब तक समान नागरिकता संहिता लागू नहीं होता तब तक महिलाओं को उनके अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा और अधिकार देना मुमकिन नहीं है। इसलिए हमारी सरकार UCC लागू करने के लिए तैयार है।

यूसीसी का समर्थन, लेकिन सभी पक्षों से चर्चा जरूरी: टीडीपी

टीडीपी ने यूसीसी का समर्थन किया, लेकिन चाहती है कि इसमें सभी पक्ष शामिल हों। टीडीपी संसदीय दल के नेता लावू श्री कृष्ण देवरायालु ने कहा, %हम इसका समर्थन करेंगे। अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन जब

भी हमें इसकी जरूरत महसूस होगी, हम इस पर विचार करेंगे। इसे अपनाने से पहले हम निश्चित रूप से अलग-अलग पक्षों को इसमें शामिल करेंगे। पार्टी का मौजूदा रुख उसके पहले के रेटेड से अलग है। 24 के लोकसभा

चुनाव के बाद एनडीए में शामिल होने से पहले, टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि जब यूसीसी की बात आएगी, तो टीडीपी मुस्लिम समुदाय के साथ खड़ी रहेगी।

बिहार में जदयू को राजद की सलाह

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर जारी सियासी घमासान के बीच राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने जदयू को बड़ा ऑफर दे दिया है। जदयू को उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि आइए, हम और आप मिलकर बिहार में नई सरकार बनाएं और भाजपा जैसी कथित सांप्रदायिक दलों से राज्य की जनता को मुक्ति दिलाएं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार वैसे लोगों को छोड़ें। धर्मरिपेक्ष राज्य है, यहां सभी को अपना-अपना धर्म मानने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि नीतीश के साथ कुछ ऐसे लोग लगे हुए हैं जो बर्बाद कर रहे हैं। सामाजिक न्याय वाले लोग साथ आए, भाजपा को लात मारें। इस संदर्भ में जब राजद के शीर्ष नेतृत्व से बात हुई तो उन्होंने गठबंधन के लिए स्पष्ट रूप से कुछ तो नहीं कहा, लेकिन यूसीसी पर एनडीए, विशेषकर भाजपा से उनका मतभेद उभरकर सामने आ गया। राजद नेतृत्व का कहना है कि भाजपा तत्कालिक और महत्वपूर्ण मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी जैसे मुद्दे

उछालती रही है। बिहार की प्रकृति सर्वधर्म समभाव और सामाजिक सौहार्द की रही है। यहां विभाजनकारी शक्तियों के मंसूबे कभी फलीभूत नहीं हुए और आगे भी नहीं होंगे। सभी धर्म-संप्रदाय को राजद बराबर की दृष्टि से देखता है, और सामाजिक विभाजन के किसी भी प्रयास का विरोध करेगा। उल्लेखनीय है कि बिहार में जदयू के साथ राजद दो बार सत्ता की साझेदारी कर चुका

है। वह दोनों दौर मिलाकर लगभग तीन वर्षों की साझेदारी रही है, लेकिन उस दौरान दोनों के अंतर्भेद सार्वजनिक हुए हैं। और कई एक मुद्दों पर मतभेद इतना गहरा हुआ कि सरकार परिवर्तन की नौबत आ गई। दोनों बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं और जब-जब सत्ता परिवर्तन हुआ, तब-तब वे भाजपा के पाले में आए। उन्होंने कहा है कि राजद के गठबंधन कर बिहार में सरकार बनाएं।

बिल को सीधे संसद में पेश कर पास कराया जाना चाहिए : उमर अब्दुल्ला

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) को लेकर केंद्र सरकार के रवैये की कड़ी आलोचना की। उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय महत्व वाले किसी भी कानून पर संसद में बहस होनी चाहिए और उसे वहीं पास किया जाना चाहिए, न कि अलग-अलग राज्यों के जरिए चुनिंदा तौर पर लागू किया जाना चाहिए। यहाँ पत्रकारों से बात करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि

अगर बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के पास यूसीसी पास करने के लिए सच में जरूरी संख्या बल है, तो उसे बीजेपी शासित राज्यों में प्रयोग करने के बजाय संसद के सामने इसका ड्राफ्ट पेश करना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि पूरे देश में



एक समान रूप से लागू होने वाले कानून को टुकड़ों-टुकड़ों में पेश नहीं किया जा सकता। अब्दुल्ला के मुताबिक, सरकार की रणनीति से यह सवाल उठता है कि क्या NDA में उसके सहयोगी दल भी इस कदम का पूरी तरह समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनके अपने ही लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं, तो वे कैसे कह सकते हैं कि इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए? उन्होंने आगे कहा कि जो कानून सिर्फ

बीजेपी शासित राज्यों में लागू हो, उसे एकसमान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है। अब्दुल्ला ने फिर कहा कि सिर्फ संसद ही पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है और इसलिए, यूसीसी पर अंतिम फैसला उसे ही लेना चाहिए। उनके ये बयान उत्तराखंड के यूसीसी का अपना वर्धन पास और नोटिफाई करने वाला पहला राज्य बनने के एक दिन बाद आए।

डीएमके नेता ने अमित शाह पर साधा निशाना

द्रविड़ मुनेत्र कळगम (द्रमुक) के वरिष्ठ नेता टी. के. एस. इलानगोवन ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने संबंधी बयानों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और इसे ‘‘असंवैधानिक’’ करार दिया। इलानगोवन ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की लंदन यात्रा को लेकर राज्य सरकार से पूरी पारदर्शिता बरतने की भी मांग की। उन्होंने बातचीत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा शासित राज्यों में यूसीसी लागू करना संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा, ‘‘यह भारत के संविधान के खिलाफ है। वे इसे लागू नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक भारतीय को मौलिक अधिकार के तहत किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार करने और उसका पालन करने का पूरा अधिकार देता है। अमित शाह जिस बारे में बात कर रहे हैं, वह संविधान के खिलाफ है। यह बिल्कुल गलत है।’’ केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने 13 सितंबर को घोषणा की थी कि 29 से पहले भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) द्वारा शासित सभी 21 राज्यों में यूसीसी लागू कर दी जाएगी। यूसीसी का उद्देश्य विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए सभी नागरिकों पर समान



कानूनी व्यवस्था लागू करना है, जिसमें धर्म-विशिष्ट कानूनों को हटाकर एक समान कानूनी ढांचा स्थापित किया जाएगा। इलानगोवन ने मुख्यमंत्री विजय की लंदन यात्रा को लेकर भी सत्तारूढ़ सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने संभावित औद्योगिक निवेश के संबंध में आधिकारिक कार्यक्रम या पारदर्शी यात्रा विवरण जारी नहीं किए जाने पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में पर्याप्त बुनियादी ढांचे और नीतिगत समर्थन के अभाव के कारण कई परियोजनाएं पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में चली गईं। इलानगोवन ने कहा, ‘‘सरकार की ओर से इस यात्रा का कोई कार्यक्रम जारी नहीं किया गया। हमें केवल यह बताया गया कि वह 10 सितंबर को रवाना होंगे। वह किन देशों की यात्रा कर रहे हैं और किन कंपनियों से मुलाकात करने वाले हैं, इसके बारे में कुछ भी सामने नहीं आया है।’’ उन्होंने कहा कि इसके बजाय सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री को मोटर कार रेस को हरी झंडी दिखाते हुए दिखाया गया।



Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma
@Editor_SanjayS

66

मेटा अब बच्चों के यौन शोषण और उनकी सुरक्षा से जुड़े गंभीर मामलों की जानकारी भारत की सही कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ साझा करने पर सहमत हो गया है। ऑनलाइन स्पेस में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में काम करने वाली किसी भी सोशल मीडिया कंपनी के लिए यह एक बुनियादी और गैर-समझौतावादी शर्त है।

जिद... सच की

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा जरूरी

बच्चों को लेकर सोशल मीडिया व डिजिटल प्लेटफॉर्म का सुरक्षित इस्तेमाल नहीं हो पाना वैश्विक चिंता का विषय बनता जा रहा है। इसी चिंता से जुड़ी एक याचिका पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार व संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। उधर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और हानिकारक कंटेंट को लेकर केंद्र सरकार द्वारा अपनाए गए सख्त रुख के बाद आखिरकार टेक दिग्गज मेटा झुकने को मजबूर हो गया है। मेटा अब बच्चों के यौन शोषण और उनकी सुरक्षा से जुड़े गंभीर मामलों की जानकारी भारत की सही कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ साझा करने पर सहमत हो गया है। ऑनलाइन स्पेस में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में काम करने वाली किसी भी सोशल मीडिया कंपनी के लिए यह एक बुनियादी और गैर-समझौतावादी शर्त है। इससे पहले याचिका में बच्चों द्वारा सोशल मीडिया एवं अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों के इस्तेमाल पर सुरक्षा उपायों की मांग की गई है।

याचिका में कहा गया है कि अठारह वर्ष से कम उम्र वालों का सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए अभिभावकों की सहमति अनिवार्य की जानी चाहिए। याचिका में उठाई गई चिंता को वाजिब बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी भी की है कि भारत में बच्चों के लिए कुछ सुरक्षा उपायों की सख्त जरूरत है। सबसे बड़ी चिंता इस बात की भी है कि प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों के नियम भारतीय कानून से मेल नहीं खा रहे। हमारे यहां अठारह वर्ष से कम उम्र वाले को नाबालिग की श्रेणी में रखा जाता है जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तेरह वर्ष की उम्र में भी बच्चों का अकाउंट खोलने की अनुमति देते हैं। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के विस्तार ने सभी आयु वर्ग के लिए शिक्षा, संवाद और मनोरंजन के नए अवसर खोले हैं। लेकिन इन अवसरों के साथ-साथ जोखिम भी कम नहीं है। कम उम्र में ही सोशल मीडिया पर सक्रियता बच्चों में कई तरह की शारीरिक व मानसिक व्याधियों को तो जन्म दे ही रही है, हानिकारक कंटेंट, साइबर बुलिंग व ऑनलाइन शोषण का खतरा भी मंडरा रहा है। बाल यौन शोषण सामग्री का प्रसार तो गंभीर अपराधिक और सामाजिक चुनौती बनता जा रहा है। इसी कारण न्यायपालिका भी अब डिजिटल मंचों की जिम्मेदारी, कानून के पालन और बच्चों की सुरक्षा के बीच संतुलन पर अधिक स्पष्टता चाहती दिखाई दे रही है। बहस केवल सोशल मीडिया की आयु सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण तैयार करने से जुड़ी व्यापक चुनौती है।

Sanjay

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

जलभराव का हो सकता है स्थाई समाधान

वीरेंद्र कुमार पैन्थूली

बरसात के दौरान रुक-रुक कर बस्तियों में जलभराव का संकट देखने को मिल रहा है। जिन राज्यों में चुनाव नजदीक हैं, वहां यह राजनीतिक मुद्दा बन रहा है। क्योंकि व्यापारी, विद्यार्थी, कर्मचारी व आम परिवार, सब जलभराव से परेशान हैं। कोई भ्रष्टाचारियों को कोसता है तो कोई अपने ही शहरियों को। आजकल गुरुग्राम, दिल्ली या पूरे एनसीआर का जलभराव सुर्खियों में है। दक्षिण भारत के महानगरों व मुंबई में भी यदा-कदा ऐसे 'जलप्लावन' के दृश्य दिख जाते हैं। बरसातों कम हों या ज्यादा, मानसूनी हों या न हों, हमारे नगर-महानगर, यहां तक कि गांव भी बरसाती पानी से लबालब हो जाते हैं। कई-कई दिनों तक जलजमाव हो जाता है। नगर निकाय न तो बरसाती पानी सोख पा रहे और न ही उसकी निकासी कर पा रहे हैं। अपर्याप्त और अधिकतर पुरानी, जर्जर, कचरे से अटी-पटी नाले-नालियों की ड्रेनेज प्रणाली भी इसका कारण है। आवासीय परिसरों से पंपों से पानी निकालना पड़ता है।

नावें चलने लगती हैं। शौचालय और सीवरेज लाइनें भी ओवरफ्लो हो जाती हैं। कई बस्तियां ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ी नहीं होती। इससे भी जलजमाव के नए क्षेत्र बन जाते हैं। जलजमाव हो जाए तो पानी का जमीन के भीतर जाना बंद या मंद हो जाता है। भूमिगत जल स्तर ऊंचा रहता है। ठोस कंक्रीट निर्माण के कारण पानी कम नीचे जाता है। जलवायु बदलाव के दौर में विश्व के कई महानगर 'जलप्लावन' की स्थितियां झेलते हैं। इंजीनियरिंग व्यवस्थाएं इस समस्या का निदान नहीं कर पा रहीं। इसी वजह से कई देश अपने शहरों को स्फॉन्ज सिटी बनाने में लग गए हैं। स्फॉन्ज सिटी यानी ऐसा नगर जो अतिरेकी बरसातों को स्फॉन्ज की तरह सोख ले, उसे भंडारित रखे और जरूरत पड़ने पर उपलब्ध भी करा दे। स्फॉन्ज सिटी अपने पानी को बाहर छोड़ने के बजाय अपनी सीमा के भीतर ही संभाल कर रखती है,

अपने उपयोग के लिए। इसे पार्कों, उद्यानों में सिंचाई में लगा सकते हैं। लंबे समय में स्फॉन्ज सिटीज का लाभ यह हो सकता है कि इससे उत्सर्जित कार्बन और जलवायु बदलाव के दंश कम करने में भी मदद मिले।

इनमें प्राकृतिक प्रणालियां-फ्लड प्लेन, वेटलैंड, हरित क्षेत्र-पानी को सहेजती हैं। इसके विपरीत शहरी स्टॉर्म ड्रेन या छोटी-बड़ी जल निकासी नालियों जैसे कंक्रीट ढांचों वाली शहरी ड्रेनेज व्यवस्थाएं मुख्यतया बरसाती पानी को शहर से बाहर निकालने के लिए होती हैं। कंक्रीट निर्माण जैसे-जैसे पुराने पड़ते हैं और जनसंख्या बढ़ती है, तो इनकी क्षमता बढ़ानी पड़ती है, अन्यथा शहर

अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन जैसे देश भी इसे अपनाए हुए हैं। भारत में भी चेन्नई, मुंबई, कोच्चि में महानगरीय बाढ़ों को रोकने के लिए स्फॉन्ज सिटी नियोजन, अध्ययन आदि पर काम हो रहा है। हाल ही में दिल्ली के लिए मास्टर प्लान 2047 घोषित किया है जिसमें दिल्ली का स्फॉन्ज सिटी की ओर बढ़ना नजर आ रहा है। फरवरी 2021 में बृहन्मुंबई कांफॉरिशन (बीएमसी) ने भी स्फॉन्ज सिटी लागू करना चाहा था। साल 2021 से चेन्नई ने भी खुद को स्फॉन्ज सिटी के रूप में ढालना शुरू कर दिया था। ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने बाढ़ रोकने के लिए 57 स्फॉन्ज पार्क स्थापित करना तय किया था। चीन ने 2014 से स्फॉन्ज सिटीज



डूबने लगते हैं। स्फॉन्ज सिटीज में पेड़, पार्क, झील, तालाब, वेटलैंड्स, रेन गार्डेंस, ग्रीन रूफ व पार्क-आधारित अतिवृष्टि प्रबंधन होता है। ये भारी बरसातों में कम ही समस्याग्रस्त होंगी। यह जल्दी से जल्दी नाले-नालियों की सीमेंटेड प्रणालियों से पानी बाहर करने की कामचलाऊ सोच से भिन्न, पानी को धीमे-धीमे रिसाव के माध्यम देने की सोच है। इसके मूल में बरसाती जल को रोकना और सोखना है। इससे बाढ़ विभीषिकाएं भी कम होने लगती हैं। संगृहीत जल का पुनः उपयोग होता है। स्फॉन्ज सिटीज के कार्यान्वयन को शहरों में जल-अकाल, बाढ़, जलप्लावन, हीट आइलैंड निर्माण व जैव विविधता हानियों को कम करने का जरिया माना जा रहा है। इसे क्लाइमेट चेंज अडैप्टेशन टूल माना जा सकता है। पेरू, कनाडा,

निर्माण को शहरी नियोजन का हिस्सा बना दिया था। चीन के पेकिंग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कोंगजियान यू ने ही स्फॉन्ज सिटीज के विचार को प्रतिपादित किया था। जलजमाव रोकने के लिए चीन ऐसे शहर बनाना चाहता था, वहाँ इसका कारण यह भी था कि उसके नए बसे आधे से ज्यादा शहर पानी की कमी से जूझ रहे थे।

स्फॉन्ज शहरों को लेकर चीन का लक्ष्य है कि उसके 80 प्रतिशत शहर कम से कम 70 प्रतिशत बरसाती जल का संग्रहण और उपयोग करें। भारत के लक्ष्य भी ऐसे ही होने चाहिए। जलवायु बदलाव के दौर में शहरों को विशाल स्फॉन्ज की तरह बनना होगा। प्रकृति ने तो पहले ही हमें जंगलों, घास के मैदानों, वेटलैंड्स, प्राकृतिक झीलों के रूप में प्राकृतिक स्फॉन्ज प्रदान किए हुए थे।

डॉ. रेनू सैनी

हमारी भारतीय संस्कृति में हर शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणेश का स्मरण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी का सर्वप्रथम स्मरण करने और उन्हें आमंत्रित करने से कार्य में विघ्न नहीं आते तथा सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। गणेश जी आज की युवा पीढ़ी के लिए ऐसे प्रबंधन गुरु हैं, जो अपने व्यक्तित्व और गुणों से यह बताते हैं कि बुद्धि, विवेक और चातुर्य सब पर भारी पड़ता है। बेडौल व्यक्तित्व भी गुणों के आगे मिसाल बन जाता है। आजकल अधिकतर युवा संसाधनों और व्यक्तित्व की छोटी-बड़ी कमियों के कारण तनावग्रस्त हो रहे हैं और कई बार घातक कदम तक उठा लेते हैं। उनके भीतर निराशा इस कदर छ जाती है कि वे उससे बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं करते।

यदि वे निराशा के भंवर से बाहर निकलकर देखें, तो समझ पाएंगे कि देवताओं ने भी अनेक बाधाओं को पार किया था। बाधाओं को सफलतापूर्वक पार करने के कारण ही वे देव कहलाए। जीवन में कुछ भी सहजता से नहीं मिलता। जो सरलता से मिल जाता है, उसमें वह आनंद नहीं आता, जो संघर्ष के बाद प्राप्त वस्तु में मिलता है। संघर्ष के साथ-साथ व्यक्ति के भीतर विवेक और बुद्धि का होना भी अनिवार्य है। कई बार जो कार्य बल से नहीं होते, वे बुद्धि से संपन्न हो जाते हैं। गणेश जी ने अनेक अवसरों पर अपने कार्यों से सिद्ध किया कि समस्याओं का समाधान चमत्कार से नहीं, बल्कि कर्म और बुद्धि से होता है। उनके जीवन से

अपनी सीमा को ताकत बनाना सीखें गणेश जी से

गणेश जी ने सिद्ध किया कि समस्याओं का समाधान चमत्कार से नहीं, बल्कि कर्म और बुद्धि से होता है। उनके व्यक्तित्व से सीख है कि अनुशासन, अनुकूलन और समय प्रबंधन ही सफलता निर्धारित करते हैं।

यह सीख मिलती है कि अनुशासन, अनुकूलन और समय प्रबंधन ही सफलता की नींव तैयार करते हैं। अक्सर युवा शिकायत करते हैं कि उनके पास सीमित संसाधन थे, इसलिए वे परीक्षा अथवा नौकरी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। गणेश जी को जब प्रथम पूज्य बनने की चुनौती दी गई और कहा गया कि उन्हें पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करनी होगी, तब उन्होंने अपने धीमे वाहन मूषक को लेकर कोई शिकायत नहीं की।

उन्होंने तुरंत बुद्धि का प्रयोग किया और अपनी सीमा को ही ताकत बना लिया। गणेश जी ने मूषक के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की तीन बार परिक्रमा की और कहा कि उनके लिए माता-पिता ही पूरे ब्रह्मांड से बढ़कर हैं। उनकी बुद्धिमत्ता देखकर सभी ने उन्हें प्रथम पूज्य स्वीकार कर लिया।



जब गणेश जी महाकाव्य लिख रहे थे, तब अचानक उनकी कलम टूट गई। उन्होंने न तो कलम टूटने का बहाना बनाया और न ही लेखन कार्य रोका। उन्होंने तत्काल निर्णय लेते हुए अपना एक दांत तोड़ लिया और उसे कलम की तरह प्रयोग करके महाकाव्य लिखना जारी रखा। इसी त्याग के कारण उनका नाम 'एकदंत' पड़ा। यदि ऐसी स्थिति हमारे सामने आ जाए, तो हममें से अनेक लोग समस्या का समाधान खोजने के बजाय समय बर्बाद करने लगेंगे।

आजकल कई युवा जीतने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं और कभी-कभी षड्यंत्र करने से भी नहीं चूकते। इसके विपरीत, गणेश जी ने एक बार अपने बड़े भाई कार्तिकेय के सम्मान और भाईचारे के लिए जान-बूझकर हार स्वीकार की। माता पार्वती ने जब इसका कारण पूछा, तो उन्होंने

सहज भाव से कहा, 'जहां अपनों का सम्मान और भाईचारा दांव पर लगा हो, वहां जीतकर भी हार हो जाती है। संबंधों की मिठास हर जीत से बड़ी होती है।' यह विचार आज के युवाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सीख है। गणेश जी के आंतरिक गुणों के अतिरिक्त उनका बाहरी व्यक्तित्व भी प्रबंधन का अद्भुत पाठ पढ़ाता है।

उनका मस्तक अत्यंत विशाल है, जो प्रत्येक विद्यार्थी और व्यक्ति को बड़ी सोच रखने की प्रेरणा देता है। बड़ी सोच दूरदर्शिता का परिचायक होती है और व्यक्ति को अनेक संकटों से बचाती है। उनके छोटे नेत्र जीवन में लक्ष्य के प्रति सूक्ष्म दृष्टि रखने की सीख देते हैं। सूक्ष्म दृष्टि से व्यक्ति अपने निर्णयों को अधिक सकारात्मक और प्रभावी बना सकता है। गणेश जी के कान बहुत बड़े और मुख छोटा है। उनके ये दोनों अंग प्रत्येक व्यक्ति को कम बोलने और अधिक सुनने की प्रेरणा देते हैं। आज अधिकतर लोग दूसरों को सुनाने के लिए तो तैयार रहते हैं, लेकिन जब दूसरों की सुनने की बात आती है, तो पीछे हट जाते हैं। दूसरों की बातें सुनने से व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता है, जबकि अपनी ही धुन में बोलते रहने से ज्ञान सीमित रह जाता है। सुनना किसी जादू से कम नहीं है। जस्टिस ओलिवर वेंडेल होम्स के अनुसार, 'दूसरों की बातें सुनना ही वह सबसे असरदार तरीका है, जिससे कोई व्यक्ति संसार में लोगों को साथ लेकर चल सकता है और उन्हें अपना मित्र बना सकता है।' गणेश जी का संपूर्ण व्यक्तित्व जीवन प्रबंधन का ऐसा सूत्र है, जिसके माध्यम से हर व्यक्ति सुख, स्वास्थ्य, प्रसन्नता, समृद्धि और प्रेम को अपने जीवन का हिस्सा बना सकता है।

पेट साफ न होने से फीकी पड़ने लगती है चेहरे की चमक

पाचन में होने वाली गड़बड़ी के कारण कब्ज की समस्या होना काफी सामान्य है। सामान्यतौर पर घरेलू उपचार और कुछ दवाइयों के माध्यम से यह समस्या ठीक हो जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि अगर आपको क्रोनिक कब्ज की दिक्कत है, यानी कि लंबे समय से अक्सर कब्ज बनी रहती है तो इससे आपके स्किन पर भी साइड-इफेक्ट्स हो सकते हैं? अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि क्रोनिक कब्ज की दिक्कत कुछ लोगों में एक्जिमा का कारण बन सकती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं, त्वचा की स्थितियों के आधार पर स्वास्थ्य का अंदाजा लगाया जा सकता है। पेट में होने वाली समस्याओं का असर त्वचा पर भी हो सकता है, जिसको लेकर विशेष ध्यान देने और उचित इलाज की आवश्यकता है।

कब्ज के दुष्प्रभाव

मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि हार्मोनल असंतुलन के जोखिम या कोलन की संरचना के कारण महिलाओं को कब्ज होने का खतरा अधिक हो सकता है। हालांकि पुरुषों में भी यह खतरा उतना ही अधिक पाया गया है। कब्ज की स्थिति के कारण पेट में गड़बड़ी, ठीक तरीके से मल त्याग करने में दिक्कत आदि हो सकती है। डॉक्टर कहते हैं, आहार और दिनचर्या को ठीक रखकर इस जोखिम को कम किया जा सकता है।

गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याओं का असर

त्वचा और आंत की परत दोनों, एलर्जी और रोगजनकों के खिलाफ रक्षा करते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कार्यों में कोई बाधा आती है, तो शरीर अन्य अंगों के माध्यम से विषाक्त पदार्थों को खत्म करने की कोशिश करता है जिससे त्वचा पर धब्बे, दाने और चकत्ते दिखाई देते हैं। इसके कारण त्वचा में कई अन्य समस्याएं जैसे काले घेरे, आंखों के नीचे सूजन और मुंहासे भी हो सकते हैं।



कब्ज से त्वचा में होने वाली समस्याएं

शोधकर्ताओं ने अध्ययन में पाया कि जिन लोगों को अक्सर कब्ज की समस्या बनी रहती है, उनमें एक्जिमा होने का खतरा अधिक होता है। ताइवान के 170,000 से अधिक लोगों पर किए गए एक अध्ययन में पता चला कि कब्ज वाले लोगों को अन्य लोगों की तुलना में एक्जिमा होने का जोखिम दो गुना तक अधिक हो सकता है। इसके अलावा कब्ज की वजह से शरीर में टॉक्सिन्स (हानिकारक तत्व) जमा होने लगते हैं, जो रक्त के जरिए त्वचा तक पहुंचकर कई समस्याएं पैदा करते हैं। जब पेट साफ नहीं होता, तो शरीर का मुख्य डिटॉक्स सिस्टम प्रभावित होता है। इससे आंत और त्वचा के बीच का संतुलन बिगड़ जाता है। अपशिष्ट पदार्थ बाहर न निकलने से हानिकारक तत्व दोबारा अवशोषित होते हैं। यह त्वचा के छिद्रों को बंद कर मुंहासे पैदा करता है। पेट साफ न होने से शरीर पोषक तत्वों को ठीक से सोख नहीं पाता।



कब्ज से बचाव

अगर आपको कब्ज की समस्या बनी रहती है और इस वजह से कुछ प्रकार की त्वचा संबंधी दिक्कतें भी हैं तो सबसे पहले पाचन को ठीक करने के उपाय किए जाने आवश्यक है। आहार में प्रोबायोटिक्स और फाइबर वाली चीजों को अधिक से अधिक शामिल करें, जिससे पाचन विकारों को ठीक किया जा सके। पाचन स्वास्थ्य में होने वाली गड़बड़ी त्वचा के साथ कई प्रकार की और दिक्कतों को भी बढ़ाने वाली हो सकती है। रोज 30 मिनट वॉक या योग करें ताकि आंतों की गतिविधि बेहतर हो। दिन में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीकर शरीर को हाइड्रेटेड रखें।



हंसना मजा है

बंता: तेरे घर से हमेशा हंसने की आवाज आती है, इतनी खुशी का राज क्या है? संता: मेरी बीवी मुझे जूते से मारती है, लग जाये तो वो हंसती है, नहीं लगे तो मैं हंसता हूँ!

मैंने सुना है आप बहुत कमजोर हो गए हो, फिट रहने के लिए रोज 1 चम्मच खाया करो अंबुजा सिमेंट क्योंकि इस सिमेंट में जान है!

पत्नी- शादी से पहले तुम मुझे होटल, सिनेमा, और न जाने कहाँ- कहाँ घुमाते थे, शादी हुई तो घर के बाहर भी नहीं ले जाते... पति- क्या तुमने कभी किसी को चुनाव के बाद भी प्रचार-प्रसार करते देखा है।

मास्टर जी: अगर पृथ्वी के अंदर LAVA है तो बाहर क्या है? संजू: मास्टर जी बाहर ओप्पो और VIVO है।

सर: अंग्रेजों ने चांद पर पानी और बरफ की खोज कर ली है। बताओ इससे तुमने क्या सिखा? संता: बस हमें अब सिर्फ दारु और नमकीन लेके जाना है!

हसबैंड वाईफ में लड़ाई हुई, हसबैंड घर से चला गया, हसबैंड: रात को फोन पे, खाने में क्या है, वाईफ: जहर। हसबैंड: मैं देर से आऊंगा, तुम खा कर सो जाना।

कहानी | ब्राह्मण, चोर और दानव

एक गांव में द्रोण नाम का गरीब ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण जैसे-तैसे भिक्षा मांगकर अपना गुजारा कर रहा था। उसकी गरीबी को देखकर एक यजमान को दया आ गई। उसने द्रोण को बैलों का एक जोड़ा दान में दे दिया। बैलों को गौधन मानकर द्रोण उनकी सेवा पूरी लगन के साथ करने लगा। उसे बैलों से इतना प्रेम था कि वो खुद कम खाता था, लेकिन बैलों को भरपेट खिलाता था। एक दिन चोर ने बैलों को चुराने की योजना के तहत ब्राह्मण के घर निकल गया। रास्ते में चोर का सामना एक भयानक राक्षस से हुआ। राक्षस ने पूछा, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? चोर ने कहा, मैं ब्राह्मण के बैल चोरी करने जा रहा हूँ। राक्षस बोला, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मैं उस ब्राह्मण को खाकर अपनी भूख शांत करूंगा और तुम उसके बैल ले जाना। चोर के मन में हुआ कि रास्ते के लिए एक साथी भी हो जाएगा, तो इसे साथ ले जाने में कोई बुराई नहीं है। ब्राह्मण के घर पहुंचकर राक्षस बोला, पहले मैं ब्राह्मण को खा लेता हूँ, उसके बाद तुम बैल चुरा लेना। चोर ने कहा, नहीं, पहले मैं बैल चुराऊंगा उसके बाद तुम ब्राह्मण को खाना। अगर तुम्हारे आक्रमण से ब्राह्मण जाग गया, तो मैं बैल चुरा नहीं पाऊंगा। फिर राक्षस बोला, जब तुम बैल खोलोगे, तो उसकी आवाज से भी ब्राह्मण जागकर अपनी रक्षा कर सकता है। मैं इस चक्कर में भूखा रह जाऊंगा। राक्षस और चोर दोनों इसी तरह बहस करते रहे। उसी बीच राक्षस और चोर की आवाज सुनकर ब्राह्मण जाग गया। ब्राह्मण को जागा देखकर जल्दी से चोर बोला, हे! ब्राह्मण देखो यह राक्षस आपको खाने आया है, लेकिन मैंने इससे आपको बचा लिया। इसने कई बार आपको खाने की कोशिश भी की पर मैंने ऐसा होने नहीं दिया। चोर की बात सुनकर राक्षस ने भी तुरंत कहा, नहीं ब्राह्मण, मैं आपको खाने नहीं, बल्कि आपके बैलों की रक्षा करने के लिए यहां आया हूँ। यह चोर आपके बैल चुराने आया था। खतरे को भांपते हुए ब्राह्मण ने फटाफट डंडा उठाया और दोनों को भगा दिया।

7 अंतर खोजें



जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951



पंडित संदीप आनंद शारंगी

मेघ 	कार्यक्षेत्र में उत्पादकता शानदार रहेगी और जिम्मेदारी वाला काम भी आसानी से संभाल लेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और शारीरिक ऊर्जा को वर्कआउट में लगाना लाभकारी होगा।	तुला 	कार्यक्षेत्र में काम का दबाव अधिक रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत और धैर्य आपको दूसरों से आगे ले जाएंगे। पदों के पीछे की गई मेहनत भी वरिष्ठों की नजर में आएगी।
वृषभ 	शाम को कुछ समय ध्यान और विनाश के लिए जरूर निकालें। दिमाग में आने वाले नए विचार दोस्तों और कार्यक्षेत्र में आपको चर्चा का केंद्र बना सकते हैं।	वृश्चिक 	आज आपके भीतर साहस, ऊर्जा और प्रतिस्पर्धा की भावना रहेगी। दोस्तों और सामाजिक संपर्कों का सहयोग मिलने से लंबे समय से अटके काम आगे बढ़ सकते हैं।
मिथुन 	आज आपका आकर्षण और प्रभाव लोगों को सहज ही अपनी ओर खींचेगा। दोस्तों, बड़े भाई-बहनों और पेशेवर संपर्कों से आपको अच्छा सहयोग मिल सकता है।	धनु 	आज करियर के मोर्चे पर आपकी चमक देखने को मिलेगी। काम में आपकी उत्पादकता बढ़ेगी और आपकी मेहनत से साख भी मजबूत होगी।
कर्क 	आज आपकी बातचीत का अंदाज और समझदारी सामाजिक तथा व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में आपको आगे ले जाएगी। छोटी व्यावसायिक यात्रा के भी योग बन सकते हैं।	मकर 	आज भाग्य, आत्मविश्वास और मानसिक स्पष्टता आपका साथ देंगे। तेज बुद्धि और रचनात्मक सोच के कारण कई काम उम्मीद से बेहतर तरीके से पूरे हो सकते हैं।
सिंह 	आज आपका ध्यान भविष्य की योजनाओं, करियर और आर्थिक सुरक्षा पर केंद्रित रहेगा। आपकी तेज बुद्धि और प्रभावशाली बातचीत आपको सम्मान दिलाएगी।	कुम्भ 	आज हर काम को सबके सामने लाने की जरूरत नहीं है। पदों के पीछे की गई मेहनत ज्यादा लाभ दे सकती है। आर्थिक मामलों में अनुशासन बनाए रखना जरूरी है।
कन्या 	आज आपकी समझदारी, भावनाओं को संभालने की क्षमता और व्यवस्थित तरीके से काम करने की आदत आपको सफलता दिलाएगी।	मीन 	आज आपका ध्यान साझेदारी, लोगों से संपर्क और मिलकर काम करने पर रहेगा। घर-परिवार का शांत वातावरण आपको भावनात्मक मजबूती देगा और मन प्रसन्न रहेगा।

वाणी कपूर के संग सर्वगुण सम्पन्न करेंगे इश्वाक सिंह

इन दिनों अपनी फिल्म 'गांधारी' को लेकर चर्चा में चल रहे इश्वाक सिंह ने 'पाताल लोक', 'रॉकेट बॉयज' और 'बर्लिन' जैसे प्रोजेक्ट्स में गंभीर और दमदार किरदार निभाए हैं। लेकिन अब अभिनेता एक अलग अंदाज में नजर आने वाले हैं। वह वाणी कपूर के साथ फिल्म 'सर्वगुण संपन्न' में रोमांटिक किरदार निभाते दिखेंगे। दोनों की यह पहली ऑनस्क्रीन जोड़ी होगी। फिल्म में काम करने के अनुभव को लेकर इश्वाक ने बताया, शूटिंग का अनुभव बहुत अच्छा रहा। यह एक बेहतरीन टीम थी, को-एक्टर बहुत अच्छे थे और डायरेक्टर सोनाली भी बहुत प्यारी हैं। उनके साथ काम करने में बहुत अच्छा समय बीता।

बता दें कि फिल्म की शूटिंग 2023 में पूरी हो गई थी, लेकिन रिलीज लंबे समय से टली हुई थी। इस बारे में पूछने पर अभिनेता ने कहा, देखिए, फिल्म कब रिलीज होगी, फिलहाल मेरे पास इससे ज्यादा जानकारी नहीं है। अब जब टीजर भी अनाउंस हो चुका है, मुझे पूरा यकीन है कि यह जल्द रिलीज होगी। वाणी कपूर के साथ काम करने के अनुभव पर उन्होंने कहा, वाकई मैं, फिलहाल मुझे इस फिल्म के बारे में बोलने की इजाजत नहीं। पर हां, उनके साथ काम करने में काफी अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को हमारी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री पसंद आएगी।



'सर्वगुण संपन्न' की कहानी

'सर्वगुण संपन्न' की कहानी एक ऐसी लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी शक्ल एक मशहूर एडल्ट फिल्म स्टार से मिलती है। इस वजह से उसे समाज और शादी से जुड़े कई तरह के सवालों का सामना करना पड़ता है। फिल्म मजाकिया अंदाज में महिलाओं पर समाज की उम्मीदों और अपनी पहचान के साथ जीने की बात करती है। फिल्म में रघुबीर यादव, बृजेंद्र काला, प्रयरक मेहता, गीता त्यागी, नामिक पॉल और श्वेता पासरिचा भी नजर आएंगे। फिल्म 5 पर स्ट्रीम होगी। निर्देशन सोनाली रतन देशमुख ने किया है।



रियलिटी शो राइज एंड फॉल सीजन 2 में होगी स्वरा भास्कर की एंट्री!

रियलिटी शो राइज एंड फॉल के दूसरे सीजन का एलान हो चुका है। वीरेंद्र सहवाग इसे होस्ट करेंगे। प्रतिभागियों के नाम के पते भी खुल गए हैं। चर्चा थी कि स्वरा भास्कर इस शो में नजर आएंगी।

अब उनके नाम की पुष्टि भी हो गई है। स्वरा भास्कर



राइज एंड फॉल सीजन 2 में नजर आने वाली हैं। उनके अलावा करण पटेल, प्रियंका चाहर चौधरी और पॉलिटिशियन शहजाद पूनावाला भी इस शो में हिस्सा लेंगे।

शो राइज एंड फॉल सीजन 2 के पहले चार कंटेस्टेंट के तौर पर स्वरा भास्कर, प्रियंका चाहर चौधरी, करण पटेल और पॉलिटिकल कमेंटेटर शहजाद पूनावाला के नामों की पुष्टि हो गई है। हाल ही में जारी प्रोमो में उन्हें 15 सदस्यों वाली लिस्ट के शुरुआती नामों के तौर पर पेश किया गया है। इस रियलिटी शो के पावर गेम में पहले मुकाबले की शुरुआत की गई है। बता दें कि क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग होस्टेड यह रियलिटी शो 26 सितंबर से एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम होगा।

राइज एंड फॉल 2 का प्रोमो काफी दिलचस्प है। इसमें होस्ट सहवाग के अलावा चारों प्रतिभागियों की झलक है। गेम में चुनौतियां काफी हैं, लेकिन सभी के तेवर तीखे हैं। प्रियंका साफ कहती हैं, राजा हो जाए रंक, जब पड़े एक नागिन का डंक। स्वरा भास्कर भी पूनावाला को शिकस्त देने की तैयारी में जुटी दिखी और आत्मविश्वास से लबरेज हैं।

आईफा अवार्ड : सलमान खान, करीना कपूर समेत कई सितारे होंगे शामिल

इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स का 27वां संस्करण 22-23 जनवरी 2027 को अबू धाबी में होगा। सलमान खान, करीना कपूर खान और शाहिद कपूर समेत कई सितारे इसमें शामिल होंगे। करण जौहर, वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, पंकज त्रिपाठी और अली फजल भी कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। दो दिन के इस इवेंट में कलाकार, फिल्ममेकर और म्यूजिक आर्टिस्ट शामिल होंगे। IIFA 2027 का आयोजन अबू धाबी के यास आइलैंड स्थित एतिहाद एरिना में होगा। अबू धाबी में IIFA का यह चौथा आयोजन होगा। कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड



टूरिज्म अबू धाबी और मिराल के साथ साझेदारी में होगा। दो दिन के इस कार्यक्रम में सितारों की परफॉर्मेंस और अवार्ड्स सेरेमनी होगी। 27वां संस्करण 2027 में यास आइलैंड के एतिहाद एरिना, अबू धाबी में आयोजित किया

फिल्म 'महाराजा' को इसकी कहानी, स्क्रीनप्ले और कलाकारों की परफॉर्मेंस के लिए काफी पसंद किया गया था। अब फिल्म की कहानी हॉलीवुड दर्शकों तक पहुंचने की तैयारी में है। इसको लेकर खुद फिल्म के प्रोड्यूसर ने बड़ी जानकारी दी है।



हॉलीवुड में बनेगा विजय सेतुपति की फिल्म का रीमेक

साल 2024 में रिलीज हुई इस क्राइम थ्रिलर का अब हॉलीवुड रीमेक बनने जा रहा है। खास बात यह है कि 'महाराजा' हॉलीवुड रीमेक पाने वाली पहली तमिल फिल्म बन गई है। फिल्म की चीन में शानदार सफलता के बाद हॉलीवुड की एक एजेंसी ने इसके रीमेक राइट्स के लिए मेकर्स से संपर्क किया है।

फिल्म के प्रोड्यूसर सुधन सुंदरम ने द टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में इस खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि हॉलीवुड की एक एजेंसी फिल्म को एक बड़े हॉलीवुड स्टार के साथ बनाने की तैयारी कर रही है। फिल्म की शूटिंग अगले साल शुरू होने की उम्मीद है। 'महाराजा' के हॉलीवुड वर्जन में लीड रोल कोन निभाएगा, इसे लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। सोशल मीडिया पर हॉलीवुड अभिनेता मैथ्यू मैककोनाही का नाम चर्चा में है, लेकिन इस खबर की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

भाग्यश्री के आरती करने से पटवर्धन परिवार में छिड़ा विवाद

गणेश चतुर्थी के दौरान सांगली के ऐतिहासिक गणपति पंचायतन मंदिर में एक्ट्रेस भाग्यश्री दसानी के जाने से पटवर्धन राजपरिवार में उत्तराधिकार को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विजयसिंहराजे पटवर्धन की तीन बेटियों में सबसे बड़ी भाग्यश्री ने मंदिर में आरती की, जिसके बाद उनके पिता ने सबके सामने दोहराया कि उनके गोद लिए बेटे आदित्यराजे ही सांगली की गद्दी के एकमात्र वारिस हैं। यह विवाद सोमवार को तब शुरू हुआ जब भाग्यश्री

पिता ने दत्तक पुत्र को घोषित किया एकमात्र उत्तराधिकारी

गणेश उत्सव के दौरान मंदिर गई। परिवार की गणेशोत्सव परंपराओं में शामिल होने के अपने फैसले के बारे में बताते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें लगा कि बेटियों में से किसी एक को आगे आना चाहिए क्योंकि उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं थी। हालांकि, विजयसिंहराजे ने इस बात को खारिज कर दिया और कहा कि वह पूरी तरह ठीक हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि भाग्यश्री ने उनकी गैर-मौजूदगी में यह रस्म क्यों निभाई और इस मौके का इस्तेमाल उत्तराधिकार पर अपना रुख साफ करने के लिए किया। पटवर्धन ने कहा, औपचारिक मूर्ति की पूजा करने का सम्मान सिर्फ मेरा और रानीसाहब (उनकी पत्नी, राजलक्ष्मीराजे पटवर्धन) का है। इसलिए, मुझे नहीं पता कि भाग्यश्री हिमालय दसानी मेरी गैर-मौजूदगी में आरती करने क्यों गईं, इसके पीछे क्या राजनीति है, या उन्हें कौन सपोर्ट कर रहा है।

मप्र में बच्चों की मौतों पर बवाल

» मुख्यमंत्री को दीये जलाने के बाद समय मिले तो राज्य की जमीनी हकीकत पर भी नजर डालें : राहुल गांधी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

भोपाल। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 30 से अधिक आदिवासी बच्चों की मौत पर पूरे राज्य में बवाल मच गया है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर करारा प्रहार किया है। राहुल गांधी ने राज्य में कुपोषण, स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली और प्रशासनिक लापरवाही को इन मौतों का जिम्मेदार ठहराया। वहीं प्रशासन ने प्रभावित इलाके में मेडिकल स्क्रीनिंग, इलाज और टीकाकरण अभियान तेज कर दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बालाघाट में 30 से ज्यादा आदिवासी बच्चों की मौत की खबरों के बाद मध्य प्रदेश सरकार की आलोचना की। उन्होंने इन मौतों के लिए राज्य में बीमारी, कुपोषण, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और साफ़ पानी न मिल पाने को जिम्मेदार ठहराया।

एक्स पर एक पोस्ट में, गांधी ने राज्य सरकार की धीमी प्रतिक्रिया और असंवेदनशीलता की निंदा करते हुए कहा कि बालाघाट में बीमारी, कुपोषण और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण 30 से ज्यादा आदिवासी बच्चों की

कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर उठाए गंभीर सवाल

राज्य में छात्र, गरीब, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग व महिलाएं सब परेशान

गांधी ने कहा कि छात्र, बच्चे, गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग और महिलाएं समेत कई समूह परेशान हैं। उन्होंने आगे कहा कि हर वर्ग को सताया जा रहा है, कोई भी खुश नहीं है। उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश

सरकार आज भारत की सबसे बुरी और सबसे अक्षम सरकार है—यही सच है। अधिकारी बालाघाट के बिस्वा ब्लॉक में आदिवासी इलाकों से बुखार, रेश और मौतों की खबरों पर कार्रवाई कर रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारी प्रभावित और आस-पास के इलाकों में

निगरानी, मेडिकल स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, इलाज और टीकाकरण अभियान चला रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मोबाइल मेडिकल यूनिट की तैनाती, अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं, रेफरल की व्यवस्था और बीमारी फैलने पर टीकाकरण शामिल है।

मौत हो गई है। संवेदनहीनता का आलम यह है कि मासूम जानें जाती रहीं, फिर भी प्रतिक्रिया धीमी रही और सरकार सोती रही। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि अगर आपको दीये जलाने और त्योहार मनाने के बाद समय मिले, तो ज़रा राज्य की ज़मीनी हकीकत पर भी नज़र डालिए। गांधी ने सरकार पर चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था, बीमारियों को रोकने में नाकामी, कुपोषण, और मिलावटी दवाओं व अवैध शराब जैसी समस्याओं

का आरोप भी लगाया। कांग्रेस नेता ने कहा कि वह मध्य प्रदेश भर में छात्रों, युवाओं और आम जनता से फ़ीडबैक लेने के लिए इंदौर जा रहे हैं। उन्होंने राज्य की शिक्षा व्यवस्था की भी आलोचना करते हुए कहा कि सामने आ रही



इंदौर में छात्रों की गूँज कार्यक्रम को लेकर घमासान

इंदौर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के छात्रों की गूँज कार्यक्रम के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण ने पार्टी से 4.3 लाख रुपये अतिरिक्त जमा करने को कहा है। कांग्रेस पहले ही 10.08 लाख रुपये जमा कर चुकी थी, लेकिन समय से पहले मैदान के इस्तेमाल पर यह मांग की गई। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक दबाव बताया है। कांग्रेस ने 19 सितंबर को यहां अपने छात्रों की गूँज कार्यक्रम के लिए सरकारी मैदान के अस्थायी लीज के तौर पर 10.08 लाख रुपये जमा किए थे, जिसके बाद इंदौर विकास प्राधिकरण ने पार्टी से लगभग 4 लाख रुपये और जमा करने को कहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मध्य प्रदेश के कमर्शियल और एजुकेशनल हब, इंदौर में स्टूडेंट आउटरीच प्रोग्राम के पांचवें एडिशन को संबोधित करेंगे। यह राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। अर्थोप्टि की ओर से इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंदू चौकसे को जारी एक लेटर में कहा गया है कि 17 से 19 सितंबर तक होने वाले छात्रों की गूँज इवेंट के लिए 12,000 वर्ग मीटर जमीन अस्थायी लीज पर दी गई थी, लेकिन साइट के निरीक्षण से पता चला कि पार्टी ने 14 सितंबर से ही इस प्लॉट के 4,800 वर्ग मीटर हिस्से का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इसके बदले में, ईडीए ने कांग्रेस से तीन दिनों की लीज फ़ीस के तौर पर अतिरिक्त 4.03 लाख रुपये का मुआवजा करने को कहा है।

भयावह घटनाएं यह दिखाती हैं कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था आज पूरे देश में सबसे ज्यादा बर्बाद हो चुकी है।

सालियान केस में कानूनी कार्रवाई करेंगे : उद्धव ठाकरे

» बोले- मेरे परिवार पर लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद आरोप

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि 2020 के दिशा सालियान मौत मामले को लेकर उनके परिवार के खिलाफ चलाया जा रहा चरित्र हनन अभियान यदि नहीं रुका तो वह कानूनी कार्रवाई करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री का यह बयान बंबई उच्च न्यायालय द्वारा सालियान की मौत की सीबीआई जांच का आदेश दिए जाने के कुछ दिन बाद आया है। अदालत ने सालियान के पिता की याचिका पर यह आदेश दिया था। इसके बाद केन्द्रीय एजेंसी ने किसी आरोपी का नाम लिए बिना मामला दर्ज किया। ठाकरे ने यहां पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, इस मामले से हमारा कोई संबंध नहीं है।



आदित्य ठाकरे भी यह कह चुके हैं। यह मुद्दा सिर्फ मेरे बारे में नहीं है। इस तरह का चरित्र हनन आप लोगों के साथ भी हो सकता है। ठाकरे ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यदि इस तरह के आरोप लगातार लगाए जाते हैं तो कोई कब तक इसे बर्दाश्त करेगा? मुझे हैरानी है कि इस मामले में मोदी और ट्रंप के नाम क्यों नहीं हैं। ठाकरे ने दोहराया कि सालियान की मौत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, लेकिन उनके परिवार का इससे कोई संबंध नहीं था। उन्होंने कहा, यह राजनीतिक रूप से प्रेरित है। हम चुप रहे क्योंकि एसआईटी मामले की जांच कर रही थी। जो लोग जांच करना चाहते हैं, वे करते रहें।

यूपीआई पर चार्ज समाज के साथ अन्याय

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने चुनिंदा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ट्रांज़ेक्शन के लिए बदले हुए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) फ़ेमवर्क का विरोध किया। उन्होंने इसे समाज के हर वर्ग के साथ बड़ी नाइंसाफी बताया और केंद्र से इस फैसले को वापस लेने की अपील की। ट्रांज़ेक्शन चार्ज पर शिवकुमार ने कहा कि मर्चेंट और व्यापारी संभवतः यह अतिरिक्त खर्च ग्राहकों पर डालेंगे। उन्होंने पत्रकारों से कहा, यह समाज के हर वर्ग के साथ बड़ी नाइंसाफी है। व्यापारी स्वाभाविक रूप से यह खर्च आम आदमी पर डालेंगे। जनता पर ये चार्ज डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी।

हम पुरजोर अपील करते हैं कि इस फैसले को वापस लिया जाए। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने भी बदले हुए फ़ेमवर्क का विरोध करते हुए कहा कि इस लेवी (शुल्क) का बोझ



आखिरकार ग्राहकों पर ही पड़ेगा। प्रेमाचंद्रन ने बताया ट्रांज़ेक्शन पर लेवी लगाने से आखिरकार आम लोगों, खासकर ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सरकार का तर्क है कि यह चार्ज दुकानदारों या व्यापारियों को देना होगा। हालांकि, इस बात की संभावना कम है कि व्यापारी खुद यह खर्च उठाएं। इसके बजाय, इसका बोझ सीधे ग्राहकों पर डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि

» कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने की केंद्र से फैसला वापस लेने की मांग

2हजार रुपये से ज्यादा के ट्रांज़ेक्शन पर प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत लेवी (अधिकतम चार्ज 300 रुपये) से ग्राहकों पर अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ेगा और उन्होंने मांग की कि इस फैसले की समीक्षा की जाए और इसे वापस लिया जाए। उन्होंने कहा 2,000 रुपये से ज्यादा के ट्रांज़ेक्शन पर 0.4 प्रतिशत की लेवी (अधिकतम चार्ज 300 रुपये प्रति माह) से ग्राहकों पर अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ेगा। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि इस फैसले की समीक्षा की जाए और इसे वापस लिया जाए। एक तरफ, भारत सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है और लोगों को कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

भारत ने टी20 सीरीज में किया क्लीन स्वीप

» अफगानिस्तान की सबसे बड़ी हार, भारत के खिलाफ 94 के न्यूनतम स्कोर पर ढेर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में 127 रन से शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने तीन मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में सात विकेट पर 221 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 14.1 ओवर में 94 रन पर ऑलआउट हो गई। अफगानिस्तान की टी20 में रनों के लिहाज से यह सबसे बड़ी हार है। अफगानिस्तान की इससे पहले टी20 में सबसे बड़ी हार इंग्लैंड के खिलाफ आई थी। 2012 में 116 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं, 2024 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम

को 104 रनों से हार मिली थी। अफगानिस्तान भारत के खिलाफ टी20 में अपने न्यूनतम स्कोर पर ऑलआउट हुआ है। इससे पहले टीम इंडिया के खिलाफ टी20 में उसने 2022 में आठ विकेट पर 111 रन बनाए थे जो उसका न्यूनतम स्कोर था। भारतीय टीम ने टी20 में 10वीं बार 100 या इससे अधिक रनों से जीत दर्ज की है। भारतीय टीम सर्वाधिक बार ऐसा करने वाली संयुक्त रूप से नंबर एक टीम बन गई है। भारत के साथ ही कनाडा ने भी टी20 में 10 बार 100+ रनों के अंतर से जीत दर्ज की है। विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान की टीम ताश के पत्तों की तरह

बिखर गई। अफगानिस्तान के लिए सिर्फ चार बल्लेबाज ही दहाई अंक तक पहुंच सके। अफगानिस्तान के लिए कप्तान इब्राहिम जादरान ने सर्वाधिक 25 रन बनाए, जबकि अजमातुल्लाह ओमरज़ई ने 17, रहमानुल्लाह गुरबाज ने 15 और नूर उल रहमान ने 11 रन बनाए। भारत की ओर से नीतीश कुमार रेड्डु और रवि बिश्नोई ने तीन-तीन विकेट



पंजाब में फिर आएगी आप सरकार : सिसोदिया

» पीएसी बैठक में आप नेता का दावा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी की नई पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी (पीएसी) की बैठक के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि पंजाब के लोग भगवंत मान सरकार के काम से खुश हैं और उन्हें दोबारा चुनना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल को कमिटी का कन्वीनर बनाया गया है और पंजाब, गोवा व गुजरात चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की गई। आप नेता ने कहा कि पंजाब के लोग भगवंत मान सरकार के कामकाज से खुश हैं और उसे दोबारा चुनना चाहते हैं, जबकि गोवा और गुजरात के वोटर बदलाव चाहते हैं।



आप की पीएमसी की पहली बैठक के बाद बोलते हुए सिसोदिया ने कहा कि राजस्थान के बारों में मिली अप्रत्याशित जीत और वहां के लोगों द्वारा भाजपा की नीतियों को नकारे जाने से हुई—जिससे यह उम्मीद जगी है कि भजपा का एक मजबूत विकल्प उभर रहा है, जिसकी लोग सक्रिय रूप से तलाश कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आप ने पंजाब, गोवा और गुजरात में होने वाले चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हम पंजाब चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लोग भगवंत मान की सरकार के कामकाज से बहुत खुश हैं और उसे दोबारा सत्ता में लाना चाहते हैं, वे भगवंत मान को फिर से मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि अगर मान मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो पुरानी पार्टियां सत्ता में वापस आ जाएंगी। उन्होंने उन पर ड्रस की समस्या फैलाने, सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल करने, रोज़गार के मामले में बेईमानी करने और व्यापारियों को लूटने का आरोप लगाया। समिति ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई के मुद्दे पर भी चर्चा की। सिसोदिया ने दावा किया कि पूरे भारत में लोग यूपीआई पर सरकार के फैसले से उगा हुआ महसूस कर रहे हैं उनका आरोप था कि यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में लिया गया था।

अभिषेक ने टी20 अंतरराष्ट्रीय में जड़ा तीसरा सबसे तेज शतक

नई दिल्ली। दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने महज 34 गेंदों में 108 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 317.64 रहा। अभिषेक ने अपनी पारी में नौ चौके और 11 छक्के लगाए। उन्होंने 30 गेंदों में शतक पूरा किया। यह भारत की ओर से लगाया गया सबसे तेज शतक है। इससे पहले यह रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम था, जिन्होंने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ 35 गेंदों में शतक लगाया था। अभिषेक का शतक टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में तीसरा सबसे तेज शतक है। उनसे आगे सिर्फ एस्टोनिया के साहिल चौहान और तुर्की के मुहम्मद फहद ने 29 गेंदों में यह कारनामा किया था। अभिषेक ने अपनी 108 रन की पारी में 102 रन सिर्फ चौकी और छक्कों से बनाए। यानी उनकी कुल पारी के 94.44 प्रतिशत रन बाउंड्रीज से आए। पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय में शतक लगाने वाले बल्लेबाज की पारी में बाउंड्रीज से आए रनों का यह सबसे बड़ा अनुपात है।

वहीं, अक्षर पटेल को दो विकेट मिले, जबकि जसप्रीत बुमराह और यश ठाकुर ने एक-एक बल्लेबाज को पवेलियन भेजा।

हाईकोर्ट ने लगाई एसबीआई को लताड़

अदालत बोली- पति के लोन की वसूली के लिए विधवा पत्नी की एफडी नहीं तोड़ सकता बैंक, पत्नी को एक लाख रुपये का मुआवजा भी देने का आदेश

» एसबीआई की ये कार्रवाई बैंकिंग नियमों का घोर उल्लंघन

» वरिष्ठ अधिवक्ता हैदर ने किया निर्णय का स्वागत

4पीएम न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साफ किया है कि बैंक मृतक पति के पर्सनल लोन की वसूली के लिए विधवा पत्नी की फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) को नहीं तोड़ सकता। कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की इस कार्रवाई को बैंकिंग नियमों का घोर उल्लंघन और चोरी-छिपे किया गया काम बताया है।

उधर इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के वकील सैयद मोहम्मद हैदर ने बढ़िया फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि इससे निराश्रित महिला को संरक्षण मिलेगा। बता



दें लखनऊ बेंच ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा मृतक पति के व्यक्तिगत ऋण की वसूली के लिए उसकी विधवा पत्नी की फिक्स डिपॉजिट (एफडी) से 19.9 लाख रुपये डेबिट करने की कार्रवाई को गंभीरता से लिया है। न्यायालय ने बैंक को पूरी रकम एफडी

की लागू ब्याज दर के साथ चार सप्ताह में वापस करने का आदेश एसबीआई को दिया है। इसके साथ ही पत्नी को एक लाख रुपये का मुआवजा भी देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने बैंक के खिलाफ गंभीर टिप्पणी भी की और इस कार्रवाई को बैंकिंग प्रक्रिया का घृणित उल्लंघन करार दिया है। न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ

कोर्ट ने गुपचुप की गई कार्रवाई बताया

न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि ऋण बीमा पॉलिसी से कवर था, जिसके लिए मृतक ने कथित तौर पर 8,803 रुपये प्रीमियम का भुगतान भी किया था। खंडपीठ ने इस पूरी प्रक्रिया को गुपचुप तरीके से की गई कार्रवाई बताते हुए कहा कि एसबीआई यह बताने में विफल रहा कि किस कानूनी प्रावधान के तहत वह पति के कर्ज की वसूली के लिए उसकी पत्नी के खाते से सीधे रकम काट सकता है।

कोविड से हुई थी पति की मौत

दरअसल याची के पति की गई 2021 में कोविड से मृत्यु के बाद एसबीआई ने सितंबर 2025 में नेहा मिश्रा को कानूनी नोटिस भेजकर 13.87 लाख रुपये के बकाया ऋण का भुगतान करने को कहा। इसके बाद बैंक ने उनका वेंतन खाता भी रोक दिया। आरबीआई लोकपाल के हस्तक्षेप के बाद ही खाते पर लगी रोक हटाई गई।

ने यह आदेश नेहा मिश्रा की याचिका स्वीकार को करते हुए दिया। उनके पति लखनऊ के रिंग रोड स्थित मेडिसिन अस्पताल में सहायक प्रोफेसर थे। उन्होंने नवंबर 2020 में एसबीआई से 15 लाख रुपये का

बैंक ग्राहकों के धन के संरक्षक

हाईकोर्ट ने कहा कि बैंक अपने ग्राहकों के धन के संरक्षक होते हैं और उसे ट्रस्ट के रूप में रखते हैं। यदि एसबीआई कानूनन मृतक के कर्ज की वसूली उसकी पत्नी से उत्तराधिकारी के रूप में करने का हक्कदार था, तब भी इसके लिए विधि सम्मत प्रक्रिया अपनानी जरूरी थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसी वसूली मनमाने, स्वेच्छाचारी और अनियमित तरीके से नहीं की जा सकती।

व्यक्तिगत ऋण लिया था। कोर्ट ने पाया कि नेहा मिश्रा न तो ऋण की सह-आवेदक थीं और न ही गारंटर अथवा क्षतिपूर्तिकर्ता या नामिनी। ऋण लेनदेन में उनका बैंक के साथ कोई संविदात्मक संबंध भी नहीं था।

दीया जलाना हिन्दू धर्म का अपमान : सौरव दास

» सीजेपी के नेता ने भाजपा पर किया प्रहार

4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आशीर्वाद का दीया जलाने की अपील पर कॉंग्रेस जनता पार्टी के नेता सौरव दास ने एक और बयान जारी है। दास ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह हिन्दू धर्म का अपमान था।



दास ने यह भी दावा किया कि लोगों ने इसे खारिज कर दिया है। दास ने लिखा कि कल दीया जलाने के कैपेन को भारत के लोगों ने बुरी तरह नकार दिया। और सही भी किया! उन्होंने लिखा कि लोगों को बेरोजगारी, नौकरी पैदा करने, पेपर लीक, शिक्षा में सुधार, खाने और पेट्रोल में मिलावट, वायु प्रदूषण, भ्रष्ट जजों वगैरह पर जवाब चाहिए। न कि किसी नेता के

जन्मदिन पर सनकी लोगों की तरह दीये जलाना! दास ने लिखा कि यह न भूलें कि यह हिन्दू धर्म का अपमान भी था।

किसी भी हिन्दू या किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति को ऐसे पवित्र दीये और आरती किसी इंसान को नहीं, बल्कि सिर्फ अपने भगवान को अर्पित करनी चाहिए। सीजेपी नेता ने लिखा कि हमेशा सत्ता में बने रहने की चाहत में, इस सरकार और इसके अंधभक्तों ने एक आम इंसान को अमर बनाने की कोशिश की है। दूसरे शब्दों में कहें तो, उन्हें भगवान के बराबर बताने की कोशिश की है।

बता दें केवल दिल्ली में पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन के अवसर पर 'आशीर्वाद का दीया' अभियान के तहत बृहस्पतिवार को यहां कर्तव्य पथ पर दीपक जलाए गए। अधिकारियों ने बताया कि कर्तव्य पथ मिट्टी के लगभग 1.25 लाख दीयों से जगमगा उठा। वहां मिट्टी के कई दीयों का इस्तेमाल करके 'आशीर्वाद का दीया' शब्द बनाए गए थे।

निठारी कांड में बरी हुए सुरेंद्र कोली ने की आत्महत्या

» फांसी के फंदे पर लटका मिला शव

4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश स्थित गौतमबुद्धनगर (नोएडा) में निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला है। आरोपी का शव हरिद्वार में मिला है। घटना उत्तरी हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र में सप्त सरोवर रोड स्थित लालमाता मंदिर के सामने की बताई जा रही है।

जानकारी के मुताबिक, कोली पिछले कुछ दिनों से यहां चाय की दुकान चला रहा था। इसी चाय की दुकान में रस्सी के सहारे उसका शव लटका मिला। सूचना मिलते ही सप्तऋषि पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण क्षेत्र के ग्राम मंगरुखाल निवासी सुरेंद्र कोली के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके परिजनों को घटना की सूचना दे दी है और मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। सुरेंद्र कोली दिसंबर 2025 में जेल से रिहा हुआ था।

न्यायाधीश संग अन्याय हो तो वह कहाँ जाए : रवि कुमार दिवाकर

» 23 दीर्घियों को फांसी की सजा सुनाने वाले जज ने व्यवस्था पर उठाए सवाल

4पीएम न्यूज नेटवर्क

मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-3/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-3 के पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर ने बृहस्पतिवार को एनडीपीएस एक्ट के 10 साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए न्याय व्यवस्था से जुड़े कई सवाल उठाए।

अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी अशोक भारत को दोषमुक्त करार दिया। फैसले में न्यायाधीश ने लिखा कि न्यायाधीश का काम न्याय करना होता है। यदि उसी के साथ अन्याय हो तो वह कहाँ जाए। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि जिला जज के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करने वाला न्यायाधीश क्या जिला जज के ऐसे आदेशों को मानने के लिए बाध्य है, जो विधि के विपरीत हों। बृहस्पतिवार को अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के 10 साल पुराने मामले में अशोक भारत को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। फैसले में अदालत ने

रिटायरमेंट से 13 दिन पहले रि कॉल पर सवाल

न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने अपने फैसले में उल्लेख किया कि इन 97 पत्रावलियों को तत्कालीन जनपद न्यायाधीश ने अपने न्यायालय में अपने रिटायरमेंट से मात्र 13 दिन पहले रि कॉल किया था। फैसले में यह भी कहा गया कि पत्रावलियों को रि कॉल करने का कोई कारण नहीं बताया गया।

फिल्म दामिनी के तारीख पर तारीख वाले संवाद का भी उदाहरण दिया। न्यायाधीश ने कहा कि एक बेकसूर व्यक्ति को न्याय हासिल करने में लंबा समय लगा। इसी फैसले में उन्होंने अपनी अदालत से 18 अगस्त को ट्रांसफर की गई हत्या के मामलों की 97 पत्रावलियों को लेकर भी सवाल उठाए। फैसले में कहा गया कि तत्कालीन जनपद न्यायाधीश ने 18 अगस्त को एक ही तरह के कुल नौ आदेश पारित किए थे। इन आदेशों के माध्यम से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी कोर्ट संख्या-3, मुजफ्फरनगर में विचाराधीन पत्रावलियों को विधि के अनुसार निस्तारण के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर की अदालत में रि कॉल किया गया।

सफाई व्यवस्था को लेकर एलएसए कंपनी पर लापरवाही का आरोप

मुख्यमंत्री के रूट पर दिखी अंधेरगद्दी, 1090 चौराहे से डालीगंज रेलवे पुल तक मुख्य मार्गों पर सफाई व्यवस्था को लेकर उठे सवाल

» नगर निगम के सरकारी कर्मचारियों को संभालनी पड़ी जिम्मेदारी

4पीएम न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित रूट पर सफाई व्यवस्था को लेकर एलएसए कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। आरोप है कि 1090 चौराहे से लेकर डालीगंज रेलवे पुल तक मुख्य मार्गों पर अपेक्षित सफाई व्यवस्था नहीं कराई गई। स्थिति यह रही कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए नगर निगम को अपने सरकारी कर्मचारियों को मौके पर उतारकर सड़कों की सफाई करानी पड़ी।

मामले की जानकारी मिलने के बाद



अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और सफाई व्यवस्था की निगरानी की। उनके साथ जोन-1 के जोनल अधिकारी ओम प्रकाश सिंह, जोनल सेनेट्री ऑफिसर कुलदीपक, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक संजीव कुमार, राहुल वाल्मीकि

समेत नगर निगम के सुपरवाइजर भी मौके पर पहुंचे और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी संभाली बताया जा रहा है कि संबंधित क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का जिम्मा एलएसए कंपनी के पास है। ऐसे में नगर निगम के सरकारी कर्मचारियों को मुख्य मार्गों की सफाई के लिए मौके पर उतरना पड़ा, जिससे कंपनी की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। नगर निगम से संबंधित कंपनी को किए जाने वाले भुगतान और उसके एवज में अपेक्षित सफाई व्यवस्था को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। नगर आयुक्त गौरव कुमार की नाराजगी के बाद कंपनी के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई तेज किए जाने की बात सामने आई है।

बताया गया कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर जिस मार्ग से आवागमन प्रस्तावित था, वहां समय रहते सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने पर नगर निगम को तत्काल अपने कर्मचारियों की मदद लेनी पड़ी। मौके पर अपर नगर आयुक्त समेत अधिकारियों की मौजूदगी में सफाई कराई गई। इस घटनाक्रम के बाद सवाल उठ रहा है कि जब मुख्य मार्गों की सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी संबंधित कंपनी को दी गई है, तो मुख्यमंत्री के रूट पर नगर निगम के सरकारी कर्मचारियों को सफाई के लिए क्यों उतरना पड़ा। अब देखना होगा कि नगर निगम इस मामले में संबंधित कंपनी की जवाबदेही तय करने के लिए क्या कार्रवाई करता है।

नीतीश की बैठक में नहीं पहुंचे ललन सिंह

4पीएम न्यूज नेटवर्क

पटना। नीतीश कुमार की आज (18 सितंबर) की बैठक में जेडीयू में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले ललन सिंह शामिल नहीं हुए। ललन सिंह की गैरमौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

ललन सिंह की अनुपस्थिति पर विधायकों ने सवाल उठाए। जब जेडीयू विधायक विनय चौधरी से इसको लेकर सवाल पूछा गया तो वह खुलकर कुछ नहीं बोले। बस इतना कहा कि अपने मंत्रालय के काम में व्यस्त होंगे। ललन सिंह की गैरमौजूदगी पर आरजेडी ने बड़ा दावा कर दिया। आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी में नूरा कुशती चल रही है। उन्होंने कहा कि ये विस्फोटक रूप लेगा और पार्टी में बड़ी टूट होगी।